जाने की संभावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो जाए। इस प्रकार के इतने बड़े तटबंधों के लिए यह जरूरी है कि इनका निर्माण चरणों में किया जाए और निर्माण के दौरान कार्यों को सुरक्षात्मक तरीकों से करने के लिए उपयुक्त सावधानियां और उपाय किए जाएं।

चूंकि बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का आयोजन और कार्यान्वयन राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, प्रभावित लोगों को अधिगृहण की गई भूमि का मुआवजा देना तथा घरों के लिए जमीन का आबंटन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस बारे में केन्द्र के पास कोई जानकारी नहीं है।

मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना

3059. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सारे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए मातृ भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : ऐसी कोई योजना नहीं है। शिक्षा मुख्य रूप से राज्य का विषय है और इस मामले में कार्यवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को है।

Import of Tractors

3060. SHRI P. M. SAYEED: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the present Government intend to import tractors to meet the demands for the same; and

(b) if so, from which country and their number?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Supply of electricity for domestic use

3061. SHRI R. K. AMIN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to supply electricity for domestic use to the resident of Sultanpuri Resettlement Colony;

(b) if so, the reasons for stoppage of work regarding laying of cables; and

(c) when Government propose to restart the work?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) The work has not started yet since financial arrangements have not been sorted out.

(c) Does not arise as the work has not started yet.

राजस्थान में चावल मिलरों द्वारा चावल के बारदाने की दर निर्धारित करना

3062. **श्री मीठा लाल पटेल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चावल मिलर लेवी चावल के मामले में बारदाने की दर प्रति क्विंटल की दर में निर्धारित करते हैं

जबकि सरकारी आदेशों के अनुसार एक बोरे में वास्तव में 95 किलो चावल भरा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बारदाने में कम की गई रकम का किसानों को भुगतान कराने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या लेवी वसूली वाले अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की नीति है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राजस्थान के चावल मिल मालिकों द्वारा जिन खाली बोरियों में लेवी चावल बेचा जाता हैं वे उनकी दरें निर्धारित नहीं करते हैं। मिल मालिकों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए सुपुर्द किए गए चावल की खाली बोरियों की प्रति क्विंटल दरें, बोरों में 95 किलोग्राम चावल भरने की क्षमता को ध्यान में रखकर, सरकार द्वारा त्रैमासिक आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह प्रथा लेवी वसूली वाले अधिकांश राज्यों में भी अपनाई जाती है।

Ceiling on Agricultural Land

3063. SHRI DHARAM VIR VASISHT: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the ceiling on agricultural land was fixed by the former Government on other considerations than the expert advice of leading agricultural experts including Punjab and Haryana Agricultural Universities;

(b) whether no marked rise in Agricultural production has taken place as a result of lowering of ceiling of agricultural land; and

(c) whether Government propose to review the results of the policy?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Fixing the ceiling on agricultural and holdings lies entirely with the State Governments. However, on the basis of the recommendations made by a conference of the Chief Ministers of the States held in 1972, the Central Government issued national guidelines on ceiling on agricultural land holdings suggesting among others the various levels of ceiling applicable to various categories of land. In framing the guidelines, all relevant factors including the social and economic were taken into consideration. Keeping in view the fact that the recommendations flowed from the consensus amongst Chief Ministers of the States, it was not considered necessary to invite and examine the expert advice of agricultural experts including Punjab and Haryana Agricultural Universities.

(b) and (c). As agricultural production is affected by a number of factors such as cultivated area, irrigation, inputs like fertilisers, improved seeds, adoption of improved technology, land reforms, price policy and weather, it is not possible to give a precise quantitative idea of the effect of a single factor such as lowering of ceiling of agricultural land on production. It may be, however, mentioned that since 1972-73, despite fluctuations from year to year, the agricultural production has registered a generally increasing trend as will be seen from the following figures:

Index number of agricultural production

(Base : Triennium ending 1961-62= 100)

1972-73	120·4
1973-74	133·3
1974-75	128·6
1975-76	148·6